साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 25-31 जुलाई 2022, वर्ष-8, अंक-16

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

चौंकाने वाला खुलसा: अपात्र किसानों की सूत्री में मध्यप्रदेश छठवें पायदान पर

फर्जी किसानों ने निकाले 4300 करोड़ मुसीबत बनी अरबों रुपए की रिकवरी

» फर्जीवाड़ा: अमस पहले, तमिलनाडु दूसरे, पंजाब तीसरे,महाराष्ट्र चौथे स्थान पर

» सिर्फ तमिलनाडु ने अपात्रों से वसूली कर 180 करोड़ केंद्र के खाते में जमा किए

अरविंद मिश्र। भोपाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से देश के 54 लाख से अधिक किसानों ने अवैध तरीके से पैसा निकाल लिया है, लेकिन, तमिलनाडु को छोड़कर कहीं सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कुल 4352 करोड़ रुपए गलत हाथों में गए, लेकिन सरकार 300 करोड़ भी नहीं वसूल पाई है। **'जागत गांव हमार'** अपने इस अंक में बता रहा है कि किस राज्य में कितने अपात्र लाभार्थी हैं। देश की सबसे बड़ी किसान योजना में भी फर्जीवाड़ा करने वालों ने सेंध लगा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में देश के 54 लाख से अधिक किसानों ने अवैध तरीके से पैसा निकाल लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 4352 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अवैध रूप से निकाल ली है। इस रकम की रिकवरी के लिए सरकार को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। बीते 22 मार्च तक अपात्र किसानों से सरकार महज 296.67 करोड़ रुपए ही वसूल पाई थी। जिसमें से 182.80 करोड़ रुपए की रिकवरी तो अकेले तमिलनाडु सरकार ने की है। जहां असम के बाद सबसे ज्यादा अपात्र किसान हैं। वहीं अपात्र किसानों की सूत्री में मध्यप्रदेश छहवें नंबर पर है। यहां कुल 3,31,061 अपात्र किसान पाए गए हैं। इसके बाद भी इनसे वसूली नहीं हो पाई है।

एसओपी भी फेल- किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक खाते में मदद भेजने वाली देश की पहली योजना में भी फर्जीवाड़ा होना सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इसलिए सरकार अपात्र किसानों से राशि वापस लेने और सरकार को राशि लौटाने के लिए एक एसओपी तैयार किया की है, लेकिन अभी इसका असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने इस स्कीम का गलत तरीके से लाभ उठाया है उन्हें हर हाल में पैसा वापस करना होगा। ताकि उसका लाभ पात्र किसानों को मिले।

राज्य	अपात्र किसान
असम	13,38,563
तमिलनाडु	7,61,465
पंजाब	6,22,362
महाराष्ट्र	4,88,593
उत्तरप्रदेश	3,32,786
मध्यप्रदेश	3,31,061
राजस्थान	3,16,364
गुजरात	2,45,314
कर्नाटक	2,09,920
आंध्रप्रदेश	1,41,563
छत्तसगढ़	1,32,380
तेलंगाना	1,21,909

तमिलनाडु के अलावा किसी राज्य ने नहीं दिखाई सख्ती

राज्यों से कृषि मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई उसके मुताबिक अवैध रूप से पैसा निकालने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन तमिलनाडु में लिया गया है। यहां अपात्र किसानों के आवेदन को मंजूरी देने के लिए 8 दिसंबर 2021 तक 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें तमिलनाडु कृषि विभाग के 8 अधिकारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने आईपीसी की धारा 409, 120, 468, 171 और आईटी अधिनियम की धारा 43 तथा 66 में दिए गए प्रावधानों के तहत 16 जिलों में एफआईआर दर्ज की है। तमिलनाडु सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से वसूली करके 180 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिए हैं। ऐसी कार्रवाई दूसरे राज्यों में नही हुई है।

गलत हाथों में गया 2.4 फीसदी पैसा

कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान स्कीम के वेब पोर्टल पर एक सुविधा भी दी है जिसके माध्यम से कोई भी किसान अवैध तरीके से लिए गए पैसे वापस कर सकता है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। दिसंबर 2018 से अब तक 10 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ की रकम दी जा चुकी है। इसका करीब 2.4 फीसदी पैसा गलत हाथों में चला गया है। देखना होगा कि 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर होने से पहले ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक लग पाती है या नहीं।

रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम

स्कीम का लाभ लेने के लिए एक दिसंबर 2019 से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पीएम-किसान के तहत धन जारी किया जा रहा है। जिसे आधार प्रमाणीकरण सहित कई स्तरों पर सत्यापित किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आधार प्रमाणीकरण लाभार्थी के पात्र होने की संभावना को बढ़ाता है, फिर भी यह पात्र होने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि कुछ अपवाद हैं जो आधार प्रमाणित होने के बावजूद लाभार्थी को अपात्र बना सकते हैं। केंद्र सरकार पात्रता का पता लगाने के लिए 5 फीसदी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रही है।

मानसून में देरी से धान का रकबा 33 फीसदी घटा

-बारिश की देरी से सोयाबीन का 9 प्रतिशत बढ़ गया

भोपाल। इन दिनों अधिकतर जिलों में बारिश सामान्य से अधिक है। लेकिन जून में कम बारिश हुई। इसके चलते किसान धान लगाने का इंतजार करने के बजाय सोयाबीन में शिफ्ट हो गए। नतीजतन प्रदेश में धान का रकबा 33 फीसदी तक घट गया। हालांकि इस दौरान सोयाबीन का रकबा करीब 9 प्रतिशत बढ़ा है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 9.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान रोपी गई है।

पिछले साल इस अवधि तक 14.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान लगाई जा चुकी थी। वहीं 45.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी हो चुकी है। वर्ष 2021 में इस अवधि तक महज 41.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की गई थी। सोयाबीन तिलहन की फसल है। अनाज की बात करें तो इस बार केवल मक्का ही पिछले साल के मुकाबले ज्यादा क्षेत्र में बोवनी की गई है। धान समेत सभी दूसरे अनाज ज्वार, बाजरा और कोदो का रकबा पिछले साल के मुकाबले कम है। दलहन की फसलों की स्थिति अनाज की तुलना में बेहतर है।

देश में 15 अगस्त तक धान का रकबा सामान्य स्तर पर पहुंच सकता है। सोयाबीन के रकबे में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। अनाज, दलहन और तिलहन का संयुक्त रकबा पिछले साल से 1.93 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इसमें खास योगदान दलहन और तिलहन का है। 15 जुलाई तक 94.51 लाख हेक्टेयर में बोवनी हो चुकी है। जबकि पिछले साल 92.58 लाख हेक्टेयर में बोवनी हुई थी।

डीएन पाठक, कार्याकारी निदेशक, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा)

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर के वाइस चांसलर भी बने सदस्य

फसल का पैटर्न बदलने और समर्थन को असरदार बनाने समिति का गठन

जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने पर फोकस

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला किया। सरकार ने एमएसपी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ाना देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा असरदार व पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। कमेटी में 16 सदस्यों को नामित किया गया है। कमेटी में दस लोगों की जगह सरकारी अधिकारियों के लिए रखे गए हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कोई नाम नहीं दिए जाने के कारण कमेटी में उसके किसी प्रतिनिधि को जगह नहीं मिली है। हालांकि, तीन स्थान उसके लिए खाली रखा गया है। यानी कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 29 सदस्य होंगे।

गजट अधिसूचना जारी

पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त सचिव (फसल) कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। सरकार ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने अन्य किसान संगठनों के पांच सदस्यों को इसमें शामिल किया है। कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञों को इसमें जगह मिली है। दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की इस कमेटी को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें अधिकांश सदस्य सरकार समर्थक हैं।

समिति के सदस्य

गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और पाशा पटेल, दिलीप संघाणी, बिनोद आनंद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के वरिष्ठ सदस्य नवीन प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्रशेखर, कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जम्मू के कुलपति डॉ. जेपी शर्मा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर के वाइस चांसलर डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन, भारत भूषण त्यागी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के डॉ. सीएससी शेखर और आईआईएम अहमदाबाद के डॉ. सुखपाल सिंह। इनके अलावा कृषि विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, और सहकारिता और वस्त्र मंत्रालय के सचिवों को कमेटी में पदेन शामिल किया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के कृषि आयुक्त भी इसमें पदेन शामिल होंगे।

-गन्ने का रकबा घटकर 53.31 लाख हेक्टेयर रह गया, -जूट और मेस्ता का रकबा 6.89 लाख हेक्टेयर पहुंचा

तिलहन का रकबा बढ़ना देश के लिए शुभ संकेत

इधर, चालू खरीफ सत्र में धान की रोपाई का रकबा अब तक 17.4 प्रतिशत कम है जबकि दलहन, मोटे अनाज और तिलहन का खेती का रकबा 7 से 9 प्रतिशत तक अधिक हो चुका है। तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी देश के लिए अच्छा संकेत है। इससे दाम को नियंत्रित करने और आयात से निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दलहन की बोवनी का रकबा 66.69 लाख हेक्टेयर से 9 प्रतिशत बढ़कर 72.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं मोटे अनाजों के बोवनी का रकबा 87.06 लाख हेक्टेयर से आठ प्रतिशत बढ़कर 93.91 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहन के तहत सोयाबीन का रकबा 90.32 लाख हेक्टेयर से 10 प्रतिशत बढ़कर 99.35 लाख हेक्टेयर हो गया है। कपास का रकबा अब तक 6.44 प्रतिशत बढ़कर 102.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। गन्ने का रकबा 53.70 लाख हेक्टेयर से मामूली रूप से घटकर 53.31 लाख हेक्टेयर रह गया है। जूट और मेस्ता का कुल रकबा मामूली गिरावट के साथ 6.89 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल की समान अवधि में 6.92 लाख लाख हेक्टेयर था।

तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी

खरीफ फसलों की बोवनी का कुल रकबा पिछले साल की इसी अवधि में 591.3 लाख हेक्टेयर था चालू खरीफ सत्र में 15 जुलाई को मामूली बढ़त के साथ 592.11 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहन का अधिक बुआई क्षेत्रफल देश के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के अलावा आयात में भी कमी आ सकती है। भारत खाद्य तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश अपनी घरेलू जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात से पूरा करता है।

सावधान! अब राज्यों में महंगे हो सकते हैं दाल-चावल

मध्यप्रदेश में 31 फीसदी घटा धान का रकबा

भोपाल। जागत गांव हमार

चावल और दालों के भाव में तेजी के आसार हैं। बीते साल के मुकाबले कम खेती इसकी सबसे बड़ी वजह होगी। जुलाई के पहले पखवाड़े तक सिर्फ धान और अरहर का रकबा घटा है, जबकि अन्य सभी फसलों की बोवनी बढ़ी है। इसके अलावा यूक्रेन संकट के चलते ज्यादातर कृषि जिंसों में उछाल के बाद गिरावट के बीच सिर्फ चावल और दालों में स्थिरता देखी गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 15 जुलाई तक धान के रकबे में 17.4 फीसदी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अब तक धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है। चावल के अलावा दालों का रुझान भी पलट सकता है। इस माह से इसमें तेजी शुरू भी हो गई है। ऑल टाइम हाई से 52 प्रतिशत गिरावट देखने वाले अरहर में 2022 के ऊंचे स्तर से अब तक 6.5 प्रतिशत तेजी आ चुकी है। खरीफ में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली दलहन अरहर का रकबा अब तक 26 फीसदी कम रहा है।

घटी चावल की सरकारी खरीद

2021-22 के रबी सीजन में चावल की सरकारी खरीद करीब 44 लाख टन हुई। इसके मुकाबले 2020-21 के रबी में 66 लाख टन और 2019-20 में 80 लाख टन चावल की खरीद हुई थी। इसके चलते इस बात की संभावना कम है कि इस साल चावल की कुल खरीद 2020-21 के लेवल यानी 135 लाख टन तक पहुंच पाएगी।

बीते साल भी कम हुआ था धान उत्पादन

ओरिगो कमोडिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव यादव ने कहा कि बीते साल भी चावल का उत्पादन घटा था। बीते कुछ महीनों से दुनियाभर में सप्लाई की किल्लत से चावल को सपोर्ट मिल रहा है। बूंदी मार्केट में 1121 सेला सफेद चावल निकट भविष्य में 9,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच सकता है जो अभी 8,600 रुपए प्रति क्विंटल है।

धान की कमी पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले

अच्छी बारिश के साथ रकबा बढ़ने की उम्मीद

इधर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मानसून की बारिश प्रगति करेगी, जो खरीफ की बुवाई के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धान के रकबे के बारे में टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 15 जुलाई तक धान की बुवाई वर्तमान खरीफ सीजन में 17.4 प्रतिशत घटकर 128.50 लाख हेक्टेयर (एलएच) रह गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 155.53 लाख हेक्टेयर थी। हालांकि दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के बुवाई रकबा 7-9 प्रतिशत अधिक है। खरीफ बोवनी के काम की प्रगति और धान के कम रकबे के बारे में पूछे जाने पर तोमर ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुझे उम्मीद है कि मानसून की बारिश आगे बढ़ेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या धान के रकबे में 17 प्रतिशत की गिरावट की भरपाई हो सकेगी, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हमें इंतजार करना चाहिए। वहीं पूर्व कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ने कहा कि धान की

बोवनी के लिए 10 अगस्त तक का समय है और इस अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त समय है।

यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश में भारी कमी

पिछले सप्ताह की तुलना में पिछले सप्ताह, धान खेती के रकबे में सुधार हुआ है। आठ जुलाई तक बोवनी 24 प्रतिशत कम थी। धान के रकबे में गिरावट की भरपाई के लिए इस महीने की बारिश महत्वपूर्ण होगी। भारत में इस मौसम में सामान्य से 14 प्रतिशत अधिक बारिश हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में वर्षा की कमी सामान्य से 65 प्रतिशत कम थी, जबकि राज्य में एक जून से 15 जुलाई के बीच सामान्य 220 मिमी की तुलना में केवल 77.3 मिमी वर्षा हुई थी। झारखंड में वर्षा की कमी 49 प्रतिशत थी जबकि बिहार में वर्षा की कमी 42 प्रतिशत थी।

दलहन का रकबा बढ़ा

खाद्यान्न श्रेणी में दलहन खेती का रकबा नौ प्रतिशत बढ़कर 72.66 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 66.69 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाज का बुवाई क्षेत्र 87.06 लाख से 8 प्रतिशत बढ़कर 93.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि मक्का का रकबा 56.69 लाख से घटकर 49.90 लाख हेक्टेयर रह गया है। बाजरा खेती का रकबा 20.88 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 34.46 लाख हेक्टेयर हो गया।

मानसून के साथ ही शुरू होती है खरीफ बोवनी

गैर-खाद्यान्न श्रेणी में, तिलहन का क्षेत्र 124.83 लाख हेक्टेयर से 7.38 प्रतिशत बढ़कर 134.04 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहन के तहत सोयाबीन का रकबा 90.32 लाख हेक्टेयर से 10 प्रतिशत बढ़कर 99.35 लाख हेक्टेयर हो गया है। कपास का रकबा अब तक 6.44 प्रतिशत बढ़कर 96.58 लाख हेक्टेयर से 102.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। गन्ने का रकबा 53.70 लाख लाख हेक्टेयर से मामूली रूप से घटकर 53.31 लाख हेक्टेयर रह गया है। जूट और मेस्टा खेती का रकबा अब तक थोड़ा कम यानी 6.89 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 6.92 लाख हेक्टेयर था। खरीफ फसलों की खेती का रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 591.3 लाख हेक्टेयर से मामूली वृद्धि के साथ चालू खरीफ सत्र में 15 जुलाई तक 592.11 लाख हेक्टेयर हो गया है।

सबसे ज्यादा बोई जाने वाली अरहर का रकबा 26 फीसदी कम

इस साल रिकॉर्ड बोवनी का अनुमान

कपास के प्रति उमड़ा किसानों का प्रेम

कपास का उत्पादन इस साल उम्मीद से काफी कम होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए 323.63 लाख गांठ की बजाय प्रोडक्शन 315.32 लाख गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम) रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, इस साल किसान इसकी बोवनी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी अगले वर्ष कॉटन उत्पादन बढ़ सकता है। किसान ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को प्याज और दूसरी फसलों के मुकाबले

कॉटन में अधिक फायदा मिला है। कॉटन का दाम उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से डबल मिला है। ऐसे में व्हाइट गोल्ड कहे जाने वाले कॉटन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में देश में कॉटन का रकबा 4 से 6 फीसदी बढ़कर 125 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। 15 जुलाई तक देशभर में कपास की बोवनी 102.8 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.2 फीसदी अधिक है।

कहां कितना कम होगा कॉटन का उत्पादन

यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 के दौरान चीन में 6.42 मिलियन मिट्रिक टन कपास का उत्पादन हुआ था। जिसे घटकर 2021-22 में 5.88 एमएमटी रहने का अनुमान है। यानी उत्पादन में रिकॉर्ड 8.5 फीसदी की कमी है। चीन दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा आयातक भी है। भारत में कॉटन उत्पादन 7.6 फीसदी कम होने का अनुमान है। यहां 2020-21 में 6.01 एमएमटी उत्पादन हुआ था, जबकि 2021-22 में 5.55 एमएमटी उत्पादन होने का अनुमान है।

कॉटन की मांग में आएगी कमी

उत्पादन कम होने के साथ ही खपत में भी कमी का अनुमान लगाया गया है। ओरिगो ई-मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण सत्संगी के मुताबिक ऊंचे भाव और सप्लाई में कमी की वजह से कॉटन की मांग में कमी रहेगी। सप्लाई की कमी की वजह से मई 2022 की शुरुआत में भारत में कॉटन का भाव 50,330 रुपए प्रति गांठ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। हालांकि कई अहम कारकों की वजह से भारत में अब कॉटन की मांग में कमी देखने को मिली है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू खपत के अनुमान को भी संशोधित करते हुए 315 लाख गांठ कर दिया है, जबकि खपत का पिछला अनुमान 320 लाख गांठ का था।

कितना हुआ एक्सपोर्ट

कमोडिटी विशेषज्ञों के मुताबिक 2021-22 के फसल वर्ष में मई 2022 तक तकरीबन 3.7-3.8 मिलियन गांठ कॉटन का निर्यात किया जा चुका है। जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 5.8 मिलियन गांठ कॉटन का निर्यात किया गया था। कॉटन की ऊंची कीमतों ने निर्यात को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना दिया है। इस साल भारत का कॉटन निर्यात 4.0-4.2 मिलियन गांठ तक सीमित रह सकता है, जबकि 2020-21 में 7.5 मिलियन गांठ कॉटन निर्यात हुआ था।

-31 जुलाई अंतिम तारीख, नहीं कराने पर रुकेगी किस्त

पीएम किसान योजना के लिए किसान करा लें ई-केवाईसी

भोपाल। जागत गांव हमार

जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ई-केवाईसी कराना जरूरी है। 31 जुलाई तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। किसान दो तरीकों से पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद आप लैपटॉप, मोबाइल से ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी घर बैठे पूरी कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें स्टेट्स

यदि किसानों ने इस स्कीम के लिए रजिस्टर किया है तो पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद फार्मर कॉर्नर में जाकर लाभार्थी सूची पर क्लिक करें। इसके बाद अपने राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करें। इसके बाद किसान को गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इस रिपोर्ट में गांव के सभी लाभार्थियों की जानकारी मिल जाएगी। इस लिस्ट में किसान अपना नाम चेक कर सकते हैं।

किसानों को मिल रहा फायदा

शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था। इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग (संयुक्त भूमि) थी। जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

ये नहीं माने जाएंगे किसान

पीएम किसान से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

कृषि विकास के लिए सहकारिता का आयाम बहुत अहम

नौ दशक पहले जब कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शुरुआत हुई तब देश की कृषि प्रकृति व भाग्य पर आधारित थी, उसे भाग्य से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने किया। सहकारिता का आयाम कृषि विकास के लिए बहुत अहम है और इसके बिना प्रधानमंत्री की किसानों की आय को दोगुना करने की परिकल्पना को हम पूरा नहीं कर सकते। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का इतिहास भारत में लगभग 9 दशक पुराना है। कृषि ऋण के दो स्तंभ हैं, लघुकालीन और दीर्घकालीन। 1920 से पहले इस देश का कृषि क्षेत्र पूर्णतः आकाशीय खेती पर आधारित था, जब बारिश आती थी तो अच्छी फसल होती थी।

1920 के दशक से किसान को दीर्घकालीन ऋण देने की शुरूआत हुई जिससे अपने खेत में कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के किसान के स्वप्न के सिद्ध होने की शुरुआत हुई। देश की कृषि को भाग्य के आधार से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने किया। उस वक्त को-ऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ी शुरूआत की। कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बैंक चरमरा गए हैं और इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

बैंकों का काम सिर्फ फायनांस करना नहीं: कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का काम सिर्फ फायनेंस करना नहीं है, बल्कि गतिविधियों का विस्तार करना है। हम सिर्फ बैंक ना चलाएं बल्कि बैंक बनाने के उद्देश्यों की परिपूर्ति की दिशा में काम करने का भी प्रयास करें।

किसान में जागरूकता लाने की कवायद: ऋण वसूली की दिशा में भी हमें तेजी लानी होगी। कार्यशालाएं, संवाद करके किसानों में इरिगेटिड लैंड का प्रतिशत, उपज, उत्पादन बढ़ाने, किसान को समृद्ध बनाने और जागरूकता लाने के लिए परिसंवाद करने होंगे। तीन लाख से ज्यादा ट्रैक्टरों को इन बैंकों ने फाइनेंस किया है, लेकिन देश में 8 करोड़ से ज्यादा ट्रैक्टर हैं। 13 करोड़ किसानों में से लगभग 5.2 लाख किसानों को हमने मध्यम और लांग टर्म फाइनेंस दिया है।

रिफॉर्म्स बैंक स्पेसिफिक ना रहे: कई नए रिफॉर्म्स बैंकों ने किए है, लेकिन रिफॉर्म्स बैंक स्पेसिफिक ना रहे, वह पूरे सेक्टर के लिए हो। एक बैंक अच्छा काम करता है तो फेडरेशन का काम है कि सारे बैंकों को इसकी जानकारी देकर उसे आगे बढ़ाने का काम करे। बैंक स्पेसिफिक रिफॉर्म्स सेक्टर को नहीं बदल सकता मगर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो गए तो सेक्टर अपने आप बदलेगा और सहकारिता बहुत मजबूत हो जाएगी।

एग्रीकल्चर फाइनेंस लकवा ग्रस्त है: एग्रीकल्चर फाइनेंस में एक दृष्टि से देश लकवा ग्रस्त हो गया है। कई जगह एक्टिविटी बहुत अच्छी चलती है और कई राज्यों में बहुत बिखर गई है। हमें इसे पुनर्जीवित करना होगा। पूंजी की कमी नहीं है, फाइनेंस करने की हमारी व्यवस्था और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गए हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ढांचा चरमरा गया नाबार्ड भी इस दिशा में एक्सटेंशन और एक्सपेंशन का एक विंग बनाएं जिससे देश में जिन किसानों को मध्यकालीन और लांग टर्म फाइनेंस चाहिए उसे मिल सके। संस्थागत कवरेज को पर्याप्त बनाना समय की मांग है। लांगटर्म फाइनेंस हमेशा शॉर्टटर्म फाइनेंस से ज्यादा होना चाहिए तभी क्षेत्र का विकास होता है। 25 साल पहले हमारे यहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस एग्रीकल्चर फाइनेंस का 50 प्रतिशत था और 25 साल बाद यह हिस्सा घटकर 25 प्रतिशत हो गया है। असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पूरा हमारा ढांचा चरमरा गया है। वर्तमान में सिर्फ 13 राज्यों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सरकार की अपेक्षा के हिसाब से चल रहे हैं।

सारे बैंक पुनर्जीवित हो: हमारा देश दुनिया में कृषि भूमि की उपलब्धता में दुनिया में सातवें नंबर पर है और कृषि एक्टिविटी की दृष्टि से अमेरिका के बाद 39.4 करोड़ एकड़ की भूमि के साथ हम दूसरे नंबर पर हैं। इतना बड़ा विशाल क्षेत्र हमारे सामने है डेवलपमेंट करने के लिए और इसीलिए नाबार्ड की स्थापना हुई। अगर 39.4 करोड़ एकड़ भूमि हम पूर्णतया इरिगेटेड कर लेते हैं तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भूख मिटाने के लिए भारत का किसान काफी है।

पैक्स कंप्यूटराइज होंगे: सहकारिता विभाग ने अभी-अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि सभी पैक्स को 2500 करोड़ की लागत से कंप्यूटराइज किया जाएगा। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड सभी एकाउंटिंग की दृष्टि से ऑनलाइन हो जाएंगे और इससे पारदर्शिता के साथ पैक्स को चलाने में फायदा होगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में भी सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने का सैद्धांतिक निर्णय किया है।

पैक्स को बहुआयामी बनाना है: पैक्स के मॉडल बाइलॉज सरकार ने भेजे हैं, सभी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े सभी कार्यकर्ताओं पैक्स के मॉडल बाइलॉज के अंदर आपके सुझाव और प्रेक्टिकल अनुभव का निचोड़ आप जरूर हमें भेजिए। हम पैक्स को बहुआयामी बनाना चाहते हैं। ये गैस वितरण, भंडारण का काम करेगी, सस्ते अनाज की दुकान भी हम ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी ले सकते हैं, एफपीओ भी बन सकता है।

कॉपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बनेगा: एक्सपोर्ट के लिए भी एक मल्टीस्टेट कॉपरेटिव का एक्सपोर्ट हाउस बनेगा और 15 अगस्त से पहले हम इसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे।

सहकारिता की स्पिरिट पुनर्जीवित करें: सरकार कितना भी पैसा डाले को-ऑपरेटिव नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर हम को-ऑपरेटिव के स्पिरिट, हमारे लक्ष्यों को पुनर्जीवित करेंगे और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी के लक्ष्य को पूरा करने में को-ऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर नहीं हमारे 'माननीय'

विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता बन गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फॉरनहाइट (अर्थात लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस) बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रोहणी पांडेय, चिंतक

भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लेकिन जलवायु परिवर्तन के जोखिम के मामले में भी दुनिया में 191 देशों में 29वें स्थान पर है। इसके बावजूद बीते 20 वर्षों में यानी 1999-2019 के बीच संसद में 895 बार 1019 सदस्यों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सवाल पूछे गए हैं। यह संसद में इन 20 वर्ष की अवधि में कुल पूछे गए सवालों का महज 0.3 फीसदी है। सबसे दिचलस्प यह है कि संसद में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सर्वाधिक सवाल कुछ चुनिंदा वर्षों में पूछे गए। यानी जिस वर्ष जलवायु परिवर्तन से जुड़े कोई निर्णय, नीति या फैसला लिया गया। 2006 में जहां 8 सवाल पूछे गए थे वहीं, 2007 में 53 सवाल जलवायु परिवर्तन पर पूछे गए थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 2007 में जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की गई थी। इसके अलावा सर्वाधिक 104 सवाल 2015 में पूछे गए थे।

इस वर्ष केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के काम का विस्तार करते हुए उसके नाम को बदलकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया गया। यह नतीजे बंग्लुरू में स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनिबिलिटी विभाग की सीमा मुंडोली, जुबिन जैकब, रंजिनी मुरली और हरिनी नागेंद्र के साथ यूएसए के स्नो लेपर्ड ट्रस्ट ने इस मुद्दे पर क्लाइमेट चेंज द मिसिंग डिस्कोर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट नामक अध्ययन में प्रकाशित किया है। यह शोधपत्र एनवॉयरमेंटल रिसर्च-क्लाइमेट में प्रकाशित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिन राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक जोखिम है वहां के सांसद सदन में संसदीय सवालों के जरिए ज्यादा आवाज उठाएंगे लेकिन शोधार्थियों को ऐसा नहीं दिखा। यह भी माना जाता है कि महिला सांसदों को इस बारे में और ज्यादा आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का और भी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन महिला सांसदों ने भी बहुत कम सवाल उठाए क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। अध्ययन में कहा गया है कि बीते 20 वर्षों में चरम मौसमी घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन इसकी तुलना में संसदीय सवालों में कोई बढ़त नहीं देखी गई। सिर्फ छह सवाल ऐसे किए गए जो कि सामाजिक-आर्थिक कमजोर वर्ग और जलवायु न्याय से जुड़े हुए थे। किस तरह के सवाल सांसदों ने पूछे हैं, इस मुद्दे पर अध्ययन बताता है कि 27.6 फीसदी सवाल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर, 23.5 फीसदी पलायन पर पूछे गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर अनुकूलन (एडॉप्टेशन) को लेकर सबसे कम 3.9 फीसदी सवाल पूछे गए हैं, जबकि भारत में इस विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा ज्यादातर सवाल जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पूछे गए हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 17 फीसदी है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के तटीय क्षेत्रों में प्रभाव और स्वास्थ्य पर पड़े वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन से जड़े अन्य मुद्दों को बहुत ही कम या न के बराबर संसद में पूछा गया है। सांसद जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवालों का जवाब कहां से हासिल करते हैं, इस पर अध्ययन बताता है कि वे केवल 10 फीसदी संसदीय सवालों के जवाब को अपनी जानकारी का स्रोत बनाते हैं। इसके अलावा 58.9 फीसदी अन्य शोध पत्रों, समाचार पत्र के आर्टिकल (22 फीसदी), कान्फ्रेंस से 11 फीसदी, संस्थानों से 5.6 फीसदी और अंतरराष्ट्रीय करारों से 1.1 फीसदी जानकारी जुटाते हैं। अध्ययन ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि जलवायु परिवर्तन की जिस स्तर की समस्या है उस अनुपात में संसद में बहुत कम सवालों का प्रतिनिधित्व है। वहीं प्रभावित राज्यों से सवाल बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं जबकि एडॉप्टेशन को लेकर चिंताएं भी बहुत कम नजर आती हैं।

वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विकसित की स्वदेशी तकनीक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है।

यहां यह बताना जरूरी है कि तटीय इलाकों के साथ-साथ समुद्र के किनारे स्थित कस्बों और गांवों में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यह पीने योग्य नहीं है, इसे पीने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि समुद्र का पानी अक्सर खारा और अन्य खनिजों से भरपूर होता है। इसके परिणामस्वरूप, इसे पीने से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए भी इस पानी को पीने के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।

इस तरह समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के साधन खोजने के लिए निरंतर शोध किए गए हैं जो पीने, खाना पकाने और अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकता है।

इसी को लेकर राज्यसभा में डॉ. सिंह ने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) की मदद से समुद्र के पानी रूपांतरण के लिए कम तापमान तापीय विलवणीकरण (एलटीटीडी) तकनीक विकसित की है।

यह ऐसी स्वदेशी तकनीक है जो प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को गर्म कर खारेपन को अलग कर देती हैं। इस तकनीक से समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है। वर्तमान में इस संयंत्र को लक्षद्वीप द्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

कम तापमान तापीय विलवणीकरण (एलटीटीडी) तकनीक पर आधारित खारेपन को दूर करने वाले तीन संयंत्रों को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगाती और मिनिकॉय द्वीपों में लगाया गया है। कम तापमान तापीय विलवणीकरण (एलटीटीडी) संयंत्रों में से हर एक की क्षमता हर दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी में बदलने की है।

इन संयंत्रों की सफलता को देखते हुए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने वैज्ञानिकों को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1.5 लाख लीटर हर दिन की क्षमता वाले अमिनी, एंड्रोथ, चेटलेट, कदमत, कल्पेनी और किल्टन में 6 और एलटीटीडी संयंत्र स्थापित करने का काम सौंपा है।

कम तापमान तापीय विलवणीकरण (एलटीटीडी) तकनीक को लक्षद्वीप द्वीप के लिए उपयुक्त पाया गया है जहां समुद्र की सतह के पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का जरूरी तापमान का अंतर है, जो लक्षद्वीप के तटों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है।

उन्होंने बताया कि खारे पन को दूर करने के संयंत्र की लागत अन्य बातों के साथ-साथ कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें उपयोग होने वाली तकनीक और संयंत्र का स्थान शामिल है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में छह एलटीटीडी संयंत्रों की कुल लागत 187.75 करोड़ रुपए है।

प्रदेश में 3000 महिलाओं को दिया जा चुका प्रशिक्षण

पशुओं का इलाज करेंगी समूह की महिलाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है। अब स्व-सहायता समूह की महिलाओं को पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वे पशुओं के टीकाकरण में भी मदद करेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पशुपालकों को इलाज के लिए अपने पशुओं को गांव से बाहर दूसरे स्थान पर न ले जाना पड़े। जिला स्तर पर करीब तीन हजार महिलाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब 23 जुलाई को भोपाल में राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें इनमें से चुनिंदा महिलाओं को बुलाकर इलाज के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। देश में सबसे ज्यादा 18.7 मिलियन गोवंशीय पशु मध्य प्रदेश में हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2020 में देश स्तर पर कराई गई गिनती में सामने आया है। इसके बाद राज्य सरकार को पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। क्योंकि ग्रामीण अंचल से समय पर टीकाकरण और इलाज न होने के कारण पशुओं की मौत ज्यादा होने की जानकारी आ रही है। इस काम में अब स्थानीय महिलाओं को जोड़ा जा रहा है।

जिला स्तर पर होगा चयन

समूहों की ऐसी महिलाओं का चयन किया जाएगा, जो पशु चिकित्सा में रुचि रखती हैं और विज्ञान विषय के साथ हायर सेकंडरी उत्तीर्ण हों। उन्हें स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सक के साथ रहकर पशुओं का इलाज करना होगा। इसके लिए पशुपालन विभाग इनको पारिश्रमिक देगा। प्रदेश में तीन लाख 40 हजार 949 स्व-सहायता समूह हैं। 39 लाख आठ हजार परिवार समूहों से जुड़े हैं।

जिला स्तर पर होगा चयन

गांवों में नियुक्त की जाने वाली ये प्रशिक्षित महिलाएं पशुपालकों को उद्यमिता विकास के तहत कर्ज दिलाने में मदद करेंगी। पशुओं के कान की टेगिंग को चिन्हित कर इनाफ पोर्टल पर दर्ज करने, पशुधन बीमा आदि कार्यों में सहायता करने के साथ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग और पशुपालकों को आय के साथ बढ़ाने की जानकारी उपलब्ध कराएंगी।

इनका कहना है

करीब तीन हजार महिलाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें से चुनिंदा महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। ये सदस्य दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। योजना जल्द ही व्यापक स्तर पर नजर आएगी।

एमएल, बेलवाल, प्रबंध संचालक
राज्य आजीविका मिशन

ए-हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम में पशु-सखियों ने साझा किए अपने अनुभव

भोपाल। प्रशासन अकादमी, भोपाल में हुए प्रशिक्षण में पशु-सखियों ने जिस तरह से अपने घर की देहरी से बाहर कदम न रखने वाली जिंदगी का हवाला देते हुए बताया कि अब वह किस तरह 30-30 किलोमीटर तक कार्यवश भ्रमण करने के साथ अन्य राज्यों में भी पशुपालन का प्रशिक्षण देने और लेने भी जाती हैं। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि आपकी लगन और उत्साह को देख कर समझ में आ रहा है कि मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश के टॉप-थ्री राज्यों में पहुंचाने में आपका कितना बड़ा योगदान है।

शहडोल जिले के करकटी गांव की पुष्पा कचेर ने बताया कि वह पशुपालन में मास्टर ट्रेनर के साथ सीआरपी का काम भी करती हैं। पशु-सखी दीदियों के साथ गांव में पाठशाला लगाती हैं। उन्होंने बताया कि वह गाय-भैंस ही नहीं, बकरी, सुअर, मुर्गा-मुर्गी आदि का भी टीकाकरण करवाने के साथ पालकों को मनरेगा, गौशाला, मुर्गी-पशु शेड निर्माण में भी लाभ दिलवाती हैं। इससे स्थानीय महिलाओं की अतिरिक्त आय बढ़ी है और दुग्ध एवं पोल्ट्री उत्पादन बढ़ा है। श्रीमती कचेर प्रदेश के कई जिलों के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनिंग दे चुकी हैं। उनके स्व-सहायता ग्रुप की 75 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी एक लाख रूपये को पार कर चुकी है।

शिवपुरी जिले के खनियाधाना की विशाखा लोधी ने बताया कि वह 7 साल से स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। पहले कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला था, अब सब जगह जा-आ सकती हैं। लोगों से बातचीत करना आ गया है और प्रतिमाह पशुपालन से 7-8 हजार रूपये की और सोशल ऑडिट से 12 हजार की आमदनी कर लेती हैं। परिवार का जीवन-स्तर बढ़ चुका है। समझाइश से गांव के लोगों का दुग्ध उत्पादन प्रति गाय-भैंस 2 लीटर से बढ़कर 10 लीटर हो गया है। उन्होंने अपेक्षा की कि हमें दूसरे प्रदेशों में हुए अच्छे काम देखने का मौका भी मिलना चाहिए।

भोपाल जिले के रतुआ गांव की रिंकल ने कहा कि वर्ष 2017 से स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। पशुपालन से न केवल अतिरिक्त आय हो रही है, घर के बच्चों को शुद्ध दूध, दही, मठा भी मिल रहा है, जिससे उनका विकास भी अच्छा हो रहा है। जरूरी नहीं कि पढ़े-लिखे लोग ही रोजगार करें, अनपढ़ भी शासकीय मदद से पशुपालन के क्षेत्र में अच्छी आय ले सकते हैं।

रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज की पशु-सखी शाहीन खान ने बताया कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में वर्ष 2016 में पति को खोने के बाद पशुपालन और कुक्कुट विकास निगम से मिले चूजों से उन्हें सहारा मिला। आज वह एक किराने की दुकान भी चलाती हैं और आत्म-निर्भर होने के साथ एक आत्म-विश्वास भी महसूस करती हैं।

श्योपुर जिले के ग्राम अगरा की पशु-सखी ने बताया कि उनकी गौशाला में 130 गाय हैं और उनकी उन्नत आर्थिक स्थिति गाँव वालों को भी प्रेरित कर रही है।

ड्रोन के माध्यम से खेत में बीज भी डाले जा सकते हैं

कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

कृषि से लाभ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तकनीकों को कृषि के क्षेत्र में अपनाया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से भी किसानों को कृषि क्षेत्र में लाभ मिलेगा इसलिए अभी ड्रोन तकनीक का परीक्षण कृषि क्षेत्र में शुरू किया गया है। सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी इस दौरान मौजूद - कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने बटन दबाकर ड्रोन से छिड़काव शुरू किया और वहां उपस्थित कृषि विभाग के उपसंचालक, पशुपालन विभाग के उपसंचालक और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भार्गव से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को ड्रोन तकनीक के बारे में जानकारी दी जाए।

विशेषकर जो बड़े किसान हैं उनके लिए यह लाभकारी साबित हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद किसानों से भी इस बारे में उन्होंने चर्चा की। ड्रोन के माध्यम से खेत में बीज डाले जा सकते हैं इससे कम समय में बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा। अब धीरे-धीरे कृषि के क्षेत्र में यह तकनीक शुरू हो गई है। कृषि विज्ञान केंद्र में इसका परीक्षण किया गया। दिल्ली की टीम को इसका काम दिया गया है। सोमवार को यह टीम जिले में आयी और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर यह परीक्षण किया।

सहजन के बीज ड्रोन के माध्यम से खेतों में डाला जाएगा

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, एडीएम नीतू माथुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वहां मौजूद रहे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी देखें कि उनके विभाग में किस प्रकार इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अभी सहजन के बीज तैयार किए जाएंगे। उन्हें ड्रोन के माध्यम से खेतों में डाला जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को जानकारी दें जिससे वह किसान इसका उपयोग कर सकें। विशेषकर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में यह बहुत उपयोगी हो सकता है।

मंत्री कमल पटेल ने कहा-मार्कफेड के एमडी को निर्देशित किया है, जल्दी टेंडर कराए जाएंगे

माफिया पर नकेल कसने की तैयारी सरकार तय करेगी पेस्टीसाइड का रेट

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ब ी खबर, जल्द तय होंगी पेस्टिसाइड की कीमत

भोपाल. मध्य प्रदेश में जल्द पेस्टिसाइड की कीमत तय की जाएगी। इसको लेकर कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल पेस्टिसाइड के रेट तय नहीं होने के कारण किसानों को मनमाने दाम पर खरीदारी करना पड़ रही है। ऐसे में कृषि मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पेस्टिसाइड की कीमत मार्कफेड तय करता है। मैंने मार्कफेड के एमडी को निर्देशित किया है। इसके जल्दी टेंडर कराए जाएंगे। पेस्टिसाइड पुराने रेट पर ही अभी मिल रहा है। इसलिए किसानों को कोई नुकसान नहीं है। नए रेट आएंगे तो बढ़ के आयेंगे।

पिछले 5 साल से पेस्टिसाइड के रेट तय नहीं होने के कारण एमपी में खाद माफिया का दबदबा बताया जा रहा है। सरकार सालों बाद भी पेस्टीसाइड की कीमत तय नहीं कर पाई है। पांच साल बाद हाल ही में पेस्टीसाइड-केमिकल की दरें तय करने निकाला गया टेंडर 24 घंटे में निरस्त किया गया था।

खाद माफिया में कसेगी नकेल: फसलों में डालने वाली अलग-अलग तरह की कीटनाशक दवाओं के केमिकल का रेट तय नहीं होने के कारण खाद माफिया इन्हें मनमाने दामों पर किसानों को बेचते हैं। सालों बाद भी कृषि विभाग इनके दामों को तय नहीं कर पाया है।

कांग्रेस ने उठाया सरकार पर सवाल: अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार का बचाव कर रही है तो कांग्रेस सरकार की नीति और रीतियों पर सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा का कहना है कि सरकार को जल्द ही कीमतों का निर्धारण कर देना चाहिए। कीमतों का निर्धारण नहीं होने से किसानों के

किसानों-आम जनता के लिए विभाग की बड़ी तैयारी,

भोपाल। किसानों के जीवन को सरल करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार लगातार प्रयासरत है। वही नवीन नीतियां भी तैयार की जा रही है। इसी बीच किसानों और भूमि स्वामी को अपने भू- अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें पटवारियों को अपने काम करवाने के लिए देने वाली रिश्वत से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल आम जनता की सुविधा के लिए भू- अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका को किओस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर सहित अपने स्वयं के फोन से निर्धारित शुल्क की अदायगी कर प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ सीधे-सीधे भूमि स्वामी और किसानों को मिलेगा। अब उन्हें भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्ति के लिए पटवारी के पास से दौड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दे किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने इसकी शुरूआत की है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के लगातार आवाहन के बाद प्रदेश के सभी विभाग में ई-तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग ने इस तकनीक का प्रयोग कर किसानों एवं आमजन को बेहतर राहत दी है। इससे पूर्व समीक्षा बैठक करते हुए सीएम शिवराज द्वारा सभी विभागों को तकनीक का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए सभी व्यवस्था को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं राजस्व विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का लाभ उठाएं और भू अधिकार पुस्तिका ऑनलाइन प्राप्त करने की कोशिश करते हुए परेशानियों से बचें। इतना ही नहीं किसानों और अन्य आम जनता को राहत देने के लिए उनके खाते के खसरा, बी-1 और ऋण पुस्तिका की प्रति भी उन्हें व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

बड़ौदी भेड़ फार्म पर ड्रोन के माध्यम से किए बीज रोपित

खेमराज मौर्य, शिवपुरी। पशुपालन विभाग के बड़ौदी फार्म पर ड्रोन तकनीकी की मदद से बीज रोपित किए गए। अभी अंकुर अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और पौधे लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सहजन के पौधे तैयार किये जा रहे हैं। दिल्ली की प्रखर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ड्रोन तकनीकी का काम सौंपा गया है।

यह टीम जिले में आकर काम कर रही है। अभी एक दिन पहले कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया था और मंगलवार को उसी दौरान सीएमओ शैलेश अवस्थी को बीज बॉल तैयार कराने के निर्देश दिए गए थे जिसे ड्रोन के माध्यम से बड़ौदी स्थित फार्म पर रोपित किया गया है। इस दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली से आई टीम से इस बारे में चर्चा की और जानकारी ली और कहा की ड्रोन तकनीक का उपयोग कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार से किया जा सकता है। इससे किसानों को आने वाले समय में लाभ होगा। शिवपुरी ऐसा पहला जिला है जहां इस प्रकार का नवाचार किया जा रहा है।

इस तकनीकी के माध्यम से बड़े किसानों को अवश्य ही लाभ मिलेगा। उन्होंने कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इस प्रकार के नवाचार के बारे में किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाए ताकि किसान भी इसका उपयोग बेहतर ढंग से कर सकें। इस दौरान पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ तमोरी, शिवपुरी नगर पालिका सीएमओ शैलेश अवस्थी, बीआरसी अंगद तोमर सहित पशुपालन विभाग के चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने फार्म के परिसर में पौधा लगाया और वायुदूत ऐप पर फोटो अपलोड किए। वहां उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि इसी प्रकार पौधे लगाकर सभी को वायुदूत ऐप पर फोटो अपलोड जरूर करें ताकि अंकुर अभियान में जिले की

लखनऊ आम महोत्सवः अलिराजपुर के किसान को मिला प्रथम पुरस्कार

नोमान खान। अलिराजपुर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वृहद आम महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि स्थानों से आम की 2000 प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया था। अलिराजपुर से 1100 किलोमीटर दूर लखनऊ में आयोजित मेले में जिले के 6 आम उत्पादक कृषकों ने भाग लिया। अलिराजपुर जिले की आम प्रजाति नूरजहां, रुमानी, राजापुरी ने सबको आकर्षित किया। इनमें कृषक युवराज सिंह ग्राम छोटा उंडवा को रुमानी आम में प्रथम पुरस्कार मिला। प्रदीप सिंह राठौर के राजापुरी आम को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही कृषक पार सिंह, कालू सिंह, प्रदेश सिंह, दिलीप सिंह के आम को भी सराहना मिली।

पुरस्कार उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने कृषक युवराज सिंह राठौर को दिया। आम की केसर, रुमानी प्रजातियों को दूर-दूर तक विक्रय करने में भी युवराज की भूमिका रहती है। पुरस्कार प्राप्त आम उत्पादक कृषकों से कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने मुलाकात कर प्रोत्साहित किया। आम फसल को बढ़ावा देने के लिए पिछले माह अलिराजपुर में भी आम फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें जिले की सभी 100 आम प्रजातियों को एक ही स्थान पर देखने का मौका मिला था।

उन्नत कृषकों को दिए जाएंगे पुरस्कार, आवेदन पत्र आमंत्रित

इंदौर। परियोजना संचालक ,आत्मा ,इंदौर द्वारा वर्ष 2021 -22 में कृषि की उन्नत तकनीक अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय बढ़ाने वाले किसानों/किसान समूह से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित प्रविष्टि में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इच्छुक कृषक अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन कर पुरस्कार पाने के हकदार बन सकते हैं।

जिला स्तर पर 25-25 और खंड स्तर पर दिया जाएगा 20-20 हजार रुपए: प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि, उद्यानिकी,पशुपालन,मत्स्य पालन और कृषि अभियांत्रिकी किसानों को जिला स्तर पर 25 -25 हज़ार एवं विकास खंड स्तर पर 20 -20 हजार के पुरस्कार आत्मा योजनानातर्गत दिए जाएंगे। कृषि श्रेणी हेतु आवेदन संबंधित विकास कहंद से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अन्य संबंधित कृषक उद्यान विभाग, पशु पालन विभाग,मछली पालन विभाग और कृषि अभियांत्रिकी विभाग से आवेदन प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात भरे हुए आवेदन 31अगस्त के शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यालय में जमा कराएं।

विनेगा में रोपे गए पौधे बताया पौधरोपाण का महत्व

शिवपुरी। जागत गांव हमार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार के निर्देशन में एवं सचिव/ जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अध्यक्षता में शाक्तिशाली महिला संगठन शिवपुरी के समन्वय से गतदिवस ग्राम विनेगा में जनजातीय समुदाय के मध्य वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह ने बताया कि इस वर्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा 15 अगस्त 2022 के मध्य लगभग दस हजार पौधे लगवाए जाएंगे। इसी क्रम में गतदिवस कार्यक्रम के शुभारंभ पर अर्चना सिंह द्वारा ग्रामजनों को फलदार वृक्ष जैसे आम, अमरूद, नीबू, सहजन, आदि के लगभग 100 पौधे वितरित किए। इस मौके पर सिंह ने बताया कि उक्त पौधे लगाने से लेकर उनका संरक्षण व संवर्धन इस प्रकार करना कि जैसे हम अपने परिवार के बच्चे का पालन पोषण करते है। साथ ही जिला न्यायाधीश ने इस अवसर पर पर्यावरण संतुलन में पौधें के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन पौधों की समय-समय पर मॉनीटरिंग की जाएगी। कार्यक्रम के पश्चात विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नि:शुल्क विधिक सहायता एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना, नालसा गरीबी उन्मूलन एवं नालसा नशा उन्मूलन विषय पर विधिक जानकारी दी गई।

मलेरियारोधी पौधे की खेती से किसानों को होगा फायदा और दवा कंपनियों की कम होगी लागत

आर्टिमिसिया की होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग

लखनऊ। जागत गांव हमार

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सहित देशभर में मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमिसिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी। इसके लिए कई कंपनियां आगे आई हैं। सीमैप ने आर्टिमिसिया की नई प्रजाति सीआईएम-संजीवनी के लिए चेन्नई की कंपनी से अनुबंध किया है। इससे एक तरफ मलेरिया की दवा बनाने के लिए विदेश से कच्चा माल नहीं मंगाना पड़ेगा तो दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नई नीति का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है।

मलेरिया की दवा तैयार की जाती है- आर्टिमिसिया पौधे में आर्टीमिसनिन नामक तत्व पाया जाता है जिससे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। आर्टीमिसनिन मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु प्लास्मोडियम फाल्सीपैरम को खत्म कर देता है। यह पौधा आमतौर पर चीन में पाया जाता है। वहां से इसे भारत लाकर नई-नई प्रजाति तैयार की जा रही है। इस पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट (सीमैप) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों ने प्रयोग किए हैं।

सीआईएम-संजीवनी में आर्टीमिसिनिन तत्व 1.2 फीसदी अधिक- सीमैप के वैज्ञानिकों ने आर्टिमिसिया की नई प्रजाति सीआईएम-संजीवनी में आर्टीमिसिनिन तत्व 1.2 फीसदी अधिक पाया। इस प्रजाति में मस्तिष्क ज्वर के साथ कैंसर सहित अन्य बीमारियों में प्रयोग होने वाली दवा बनाने वाले तत्व भी अधिक हैं। इससे खाने की गोली व इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। जर्नल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट साइंसेज में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि सीआईएम-संजीवनी किसानों और खेती से जुड़े उद्योग के लिए भी फायदेमंद है।

सीमैप से सत्व वैद नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध किया

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आर्टिमिसिया की खेती से किसानों को लगभग चार माह की अवधि में प्रति हेक्टेयर करीब 65 हजार का फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि इस पौधे को लेकर भारतीय कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के लिए आगे आ रही हैं। सीमैप के साथ चेन्नई की कंपनी सत्तव वैद नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध किया है। कंपनी आर्टिमिसिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी। साथ ही प्रसंस्करण से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देगी।

औषधीय पौधे की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नीति निर्धारण: आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि प्रदेश में कांट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नीति निर्धारित की जा रही है। मसौदा तैयार कर आयुष मंत्रालय को भेजा गया है।

खेत में ही मिलेगी उपज की कीमत

सीमैप के निदेशक प्रबोध कुमार त्रिवेदी की मौजूदगी में एमओयू पर कंपनी के प्रतिनिधि सीएसआईआर-सीमैप के प्रशासनिक अधिकारी नरेश कुमार और सत्तव वैद नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक श्रेनिक मोदी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कंपनी तैयार पौधों को किसान से लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों तक पहुंचाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज की कीमत खेत में ही मिल जाएगी। सीमैप के डॉ. मनोज ने बताया कि कई वर्षों के शोध के बाद नई प्रजाति विकसित की गई है। यह पहले से चल रही किस्म जीवन रक्षा और सीआईएम आरोग्य के बीच पॉली क्रास से विकसित किया गया है। सेंट्रल इग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीडीआरआई) ने भी अपने शोध में इस पौधे को मलेरिया रोधी दवा के लिए उपयुक्त माना है।

2027 तक मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य

प्रदेश में 2027 तक मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। कई जिलों में पिछले साल से (एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस) एपीआई की दर एक से नीचे मिली है। इस साल जून तक 26 लाख 77 हजार से अधिक सैंपल की जांच की गई, जिसमें 1077 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे ये आंकड़े को ज्यादा नहीं हैं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

केवीके ग्वालियर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार

दिव्या मिश्रा। ग्वालियर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के 94वें स्थापना दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर को कृषि के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केन्द्र प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार केन्द्रीय कृषि मंत्री, नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. के. राव एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. राज सिंह कुशवाह को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया। उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर के सभागार में भी किया गया जिसमें डॉ. वाई.पी.सिंह, निदेशक विस्तार सेवाएँ, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., डॉ. एस.एस. तोमर, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर, समस्त वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्वालियर जिले के लगभग 200 किसान उपस्थित रहे।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. तोमर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक का पुरस्कार

दतिया, भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, दतिया के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरकेएस तोमर को ''स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक पुरस्कार 2021'' से सम्मानित किया गया। पुरस्कार केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा दिया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाशचन्द्र चौधरी, नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेशचन्द्र एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेश डॉ. त्रिलोचन महापात्रा सहित परिषद, कृषि विभाग एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशकगण, कुलपतिगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सराहनीय कार्यों के लिए खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर को मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रवीन नामदेव। जबलपुर

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद,नई दिल्ली द्वारा खरपतवार अनुसन्धान निदेशालय , जबलपुर को राजभाषा हिंदी के प्रयोग -प्रसार के क्षेत्र में सर्वाधिक सराहनीय कार्यों के लिए राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया।16 जुलाई को भाकृअप के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निदेशक डॉ. जेएस मिश्र को यह पुरस्कार प्रदान किए।

राजर्षि टंडन राजभाषा का प्रथम पुरस्कार

उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के अधीन आने वाले करीब 111 संस्थानों का परिषद द्वारा पूरे वर्ष के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार -प्रसार का मूल्यांकन किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2020 -2021 के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग -प्रसार के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए खरपतवार अनुसन्धान निदेशालय,जबलपुर को राजर्षि टंडन राजभाषा का प्रथम पुरस्कार और निदेशालय की पत्रिका तृण सन्देश को गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी पत्रिका का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

वैज्ञानिक शोध कार्यों को कृषकों तक पहुंचाने में निदेशालय की हिंदी पत्रिका तृण संदेश का योगदान सराहनीय

इन पुरस्कारों की प्राप्ति पर निदेशालय के सभी कार्मिकों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आयोजित समारोह में अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति और निदेशक डॉ. जेएस मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त कर राजभाषा समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि निदेशालय में तकनीकी और वैज्ञानिक शोध कार्य किए जाते हैं, किन्तु आम कृषकों को इनकी जानकारी पूर्ण रूप से हिंदी के पर्चों और निदेशालय की हिंदी पत्रिका तृण सन्देश द्वारा दी जाती है। राजभाषा समिति के सह अध्यक्ष डॉ. पीके सिंह और प्रभारी बसंत मिश्रा ने इस उपलब्धि पर सभी कर्मचारियों के सहयोग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी आर हाडगे ने किया। आभार वित्त अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ ने माना।

खेती में विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर

2000 हजार किस्मों की खोज आईसीएआर के लिए बड़ी उपलब्धि

जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हो कृषि शोधः कृषि मंत्री तोमर

भोपाल/ नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिन्ता और चुनौती का विषय है। इससे निपटने के लिए सभी केवीके और आईसीएआर के संस्थानों तथा अन्य वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण निभानी होगी। इसके लिए रोडमैप बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि देश को परिणाम दिया जा सके और भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात की स्थितियां भी और अच्छी बन सकें। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 94 स्थापना दिवस समारोह में कृषि मंत्री ने कहा कि बीते 93 साल में आईसीएआर ने करीब 5800 फसलों और बागवानी की नई किस्मों की खोज की है। इनमें जलवायु अनुकूल व फोर्टिफाइड किस्में भी शामिल हैं। इनमें से वर्ष 2014 के बाद 2000 हजार किस्मों की खोज आईसीएआर की बड़ी उपलब्धि है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन पर नई शिक्षा नीति का उदय हुआ। अब स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम का समावेश किया जा रहा है। कृषि शिक्षा संस्थान, नई शिक्षा नीति को कैसे अंगीकार करें। यह काम आगे बढ़कर आईसीएआर ने किया है। इसका सद्परिणाम आगे देखने को मिलेगा। उन्होंने कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में काम करने सहित दलहन, तिलहन, कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी आईसीएआर व केवीके को संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने को कहा।

इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों के कुछ किसानों से कृषि मंत्री ने ऑनलाइन संवाद किया। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि के किसानों से कृषि मंत्री की चर्चा में यह बात उभरी कि सरकारी योजनाओं, संस्थागत सहयोग से इनकी आय बढ़ रही हैं, जीवन स्तर सुधर रहा है।

75 हजार किसानों की सफलता का संकलन

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि जब कृषि शोध संस्थान में बीज तैयार होता है तो किसानों को इसका भरपूर लाभ मिलता है तो उन्हें भी काफी खुशी मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी किसानों को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। तोमर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आईसीएआर ने गत वर्ष तय किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे 75 हजार किसानों से चर्चा कर उनकी सफलता का दस्तावेजीकरण किया गया है। इस अवसर पर 75 हजार की सफलता की कहानियों के संकलन की ई-बुक जारी किया गया जिनकी आय दोगुनी या इससे ज्यादा ब ी है। उन्होंने कहा कि आईसीएआर के इस स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में बनाया जाए, ताकि आज नए संकल्प लेकर किसानों की मदद की जा सके। कई किसान आईसीएआर पर भरोसा करते हैं और सरकार भी उनकी मदद करती है।

मिट्टी की जांच सबसे उपयोगी

इस अवसर पर मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए जो तकनीक बना रहे हैं, उसके साथ उनकी मदद करें न कि उनके काम में बाधा डालें। देश के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड दिया है, जो आज के समय में किसानों के लिए सबसे उपयोगी है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आईसीएआर को बधाई देते हुए कहा कि इसने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश किसानों के लिए एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें किसानों की आय, नई तकनीक, वित्तीय सहायता, फसल बीमा को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार 10 हजार एफपीओ बनाएगी, जिससे किसान आसानी से देश के किसी भी कोने में अपनी उपज बेच सकें।

भारतीय खेती की दो धाराएं

नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद ने कहा कि हरेक इन्स्टीट्यूट को अपना ऐसा संकल्प बनाना चाहिए जो सबका संकल्प बन जाये। आईसीएआर ने केवीके माध्यम से जो भी उपलब्धि हासिल की है वो लोगों को भागीदार बनाकर की है। पिछले 75 साल में ग्रीन रेव्यूलूशन का इंजन जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हुआ है। भारत सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ दो रास्तों पर चल रही है। एक ओर परम्परागत खेती पर ज़ोर दिया जा रहा है तो दूसरी ओर खेती में विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर भी पूरी ध्यान रखा जा रहा है।

फसल रोगों की रोकथाम में अधिक काम हो रहा है

इस मौके पर आईसीएआर महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि 1 से 2 अक्टूबर के बीच किसानों को कई तरह से मदद करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इससे फसलीय रोगों की रोकथाम में बहुत मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रंगीन मछली, मशीनीकरण, खाद्य और कृषि के लिए कई कदम उठाए गए हैं और भविष्य में और भी कई कदम उठाए जाएंगे। इस वर्ष, आईसीएआर ने 15 विभिन्न पुरस्कारों के तहत 92 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया, जिनमें 4 संस्थान, 1 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, 4 कृषि विज्ञान केंद्र, 67 वैज्ञानिक और 11 किसान शामिल थे, जिनमें से 8 महिला वैज्ञानिक और किसान थे।

भारतीय सब्जियों और अनाज की दुनिया भर में बढ़ी मांग

तीन महीने में 14 प्रतिशत बढ़ा भारत का कृषि निर्यात

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

देश से कृषि निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले तीन महीनों में निर्यात के आंकड़ों को देखें तो इन तीन महीनों के दौरान भारत के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात में 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। पिछले साल और इस साल के पहले तीन महीने के निर्यात को देखें तो पिछले साल पहले तीन महीने में 5,256 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था, जबकि इस साल 14 फीसदी बढ़कर निर्यात 5,987 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत 2022-23 के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए . 23 156 बिलियन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इसमें चायपत्ति, कॉफी, मसाला कपास और समुद्री निर्यात शामिल नहीं है।

ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी - कृषि निर्यात को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि देश से ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है, जबकि अनाज और विविध प्रसंस्कृत वस्तुओं जैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में 36.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। वहीं अन्य अनाजों की बात करें तो अप्रैल जून 2021 के 237 मिलियन डॉलर के निर्यात के मुकाबले इसे साल अप्रैल जून 2022 में निर्यात बढ़कर 306 मिलियन डॉलर हो गया है।

अनाज, डेयरी, मांस और पोल्ट्री निर्यात में वृद्धि

अनान और सब्जियों के अलावा डेयरी, मांस और पोल्ट्री उत्पादों में भी उछाल आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-जून 2021 में डेयरी, मांस और पोल्ट्री का निर्यात 1023 मिलियन डॉलर का था, जो अप्रैल-जून 2022 में बढ़कर 1120 मिलियन डॉलर का हो गया है। वहीं चालू वित्त वर्ष में चावल के निर्यात बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी गयी है। चालू वित्त की पहली तिमाही में चावल के निर्यात में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डेयरी, मांस और पोल्ट्री उत्पादों 9 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निर्यात के लिए बनाया गया एक इकोसिस्टम

अपीडा के अध्यक्ष एम अंगमुथु द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला में जो प्रमुख हितधारकों के सहयोग से निर्यात के लिए जरूरी इकोसिस्टम बनाया गया है, इसके माध्यम से उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में वृद्धि को बनाए रखने में सफलता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि अभूतपूर्व लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद 2021-22 में, भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात 19 192 प्रतिशत बढ़कर 50 121 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से साथ वर्चुअल बैठके आयोजित की थी। इसके साथ ही भारत में रजिस्टर्ड जीआई टैग वाले उत्पादो को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गयी है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)